PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Amar Ujala, Delhi
Mon, 19 Jun 2017, Page 9
Width: 49.21 cms, Height: 38.54 cms, a3r, Ref: 20.2017-06-19.65

दो सालों में यहीं बनने लगेंगे विशेष ग्रेड के इस्पात

आज का साक्षात्कार

चौधरी बीरेंद्र सिंह, केंद्रीय इस्पात मंत्री

इस्पात उत्पादन के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा उत्पादक बन चुका भारत अब बेहतरीन क्षमता के इस्पात बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ऐसा इसलिए ताकि ऑटो ग्रेड और रक्षा क्षेत्र में काम आने वाले इस्पात का उत्पादन देश में ही हो सके। केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का कहना है कि देश में बेहतरीन किस्म के इस्पात बनाने के लिए पूरी तैयारी हो गई है और अगले दो सालों में देश ऑटो हब बन जाएगा। संवाददाता शिशिर चौरसिया ने इन्हीं मसलों पर केंद्रीय इस्पात मंत्री से विस्तृत बातचीत की। पेश हैं इस बातचीत के अंश:

इस्पात के मामले में हम दुनिया के तीसरे बड़े उत्पादक बन गए हैं लेकिन बेहतरीन गुणवत्ता वाले इस्पात के निर्माण में अभी भी पीछे हैं। कब हम इसमें सक्षम होंगे?

हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगले दो सालों में हम इस तरह के इस्पात बनाने में सक्षम हो जाएंगे। हमने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 बना ली है। अब उपयुक्त नीतियों और फैसलों से इस तरह का माहौल तैयार किया जाएगा कि घरेलू इस्पात उद्योग फले-फूले। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत मोटर वाहनों के निर्माण का हब बन जाएगा क्योंकि इस उद्योग के लिए इस्पात देश में ही बनने लगेगा। ऐसा अनुमान है कि तब दुनिया में बनने वाली कुल कारों में भारत का हिस्सा बढ़कर 27 फीसदी हो जाएगा।

भारतीय इस्पात उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल (कोकिंग कोल) विदेशों से आता है। आयात पर निर्भरता की वजह से घरेलू उद्योग की लागत बढ़ती है। इस दिशा में क्या हो रहा है?

हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। हम अभी इस्पात उद्योग के लिए अधिकतर कोकिंग कोल विदेश से मंगाते हैं, जिसमें हजारों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। हमारी कोशिश है कि कोयला खदानों के पास ही हम कोल वाशरी बनाएं, जहां ज्यादा राख वाले कोयले की राख कम की जा सकेगी। ऐसा होने के बाद उसका उपयोग कोकिंग कोल के रूप में किया जा सकता है। ऐसा हो जाने पर इस्पात उद्योग के उपयोग के 25 से 30 फीसदी कोकिंग कोल की आवश्यकता की पूर्ति देश से ही हो जाएगी।। हमारा अनुमान है कि सिर्फ इसी से आठ-दस हजार करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी। यही नहीं, हमारा प्रयास है कि लौह अयस्क के फाइन्स का पैलेटाइजेशन किया जाए ताकि इसका भी उपयोग हो सके। अभी फाइन्स यूं ही पड़े रह जाते हैं। हमने इस्पात क्षेत्र में काम करने वाली सरकारी कंपनियों को इस दिशा में काम करने को कहा है।

आगे के वर्षों के लिए आपका क्या लक्ष्य होगा?

इस्पात क्षेत्र में हमने पहले की नीतियों को बदल कर अब घरेलू उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी कोशिश है कि हम वर्ष 2030-31 तक 30 करोड़ टन तैयार इस्पात (फिनिश्ड स्टील) का उत्पादन कर लें। इसी के लिए तो हम उन तमाम बाधाओं को दूर कर रहे हैं, जो इस मार्ग में मौजूद हैं।

आप बाधा दूर करने की बात करते हैं लेकिन आर्सेलर मित्तल और सेल के संयुक्त उपक्रम का मसला तो लंबित है?

आपने सही सवाल उठाया है। हमने इसका भी निदान ढूंढ लिया है। इस मामले में हमने करीब-करीब 99 फीसदी मसलों को सुलझा लिया है। इसके लिए मैंने खुद ही दो बैठकें की हैं। हमारी सचिव भी इस दिशा में प्रयासरत हैं। इस मामले में 31 मई अंतिम तिथि थी, जिसे तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है। उम्मीद है कि इस मसले का निदान निकल आएगा। वहां वैल्यू एडेड इस्पात का निर्माण होगा, जिसका अधिकतर उपयोग ऑटो और रक्षा क्षेत्र में होता है।

कहा जा रहा है कि नोटबंदी के दौरान इस्पात उद्योग, खास कर छोटे प्लांट को काफी दिक्कतें हुईं। क्या अब ये प्लांट उन दिक्कतों से उबर चुके हैं?

नोटबंदी के बाद ऐसे उद्योगों को कुछ दिनों तक दिक्कत हुई क्योंकि इनका अधिकतर कारोबार नकदी पर आधारित था। लेकिन यह सिर्फ अल्पकाल के लिए ही था। अब जबकि नोटबंदी का प्रभाव खत्म हो गया है, भुगतान के डिजिटल तरीके चलन में आ गए हैं तो इनका भी कारोबार पहले की तरह ही हो गया है। अब कोई दिक्कत नहीं है।

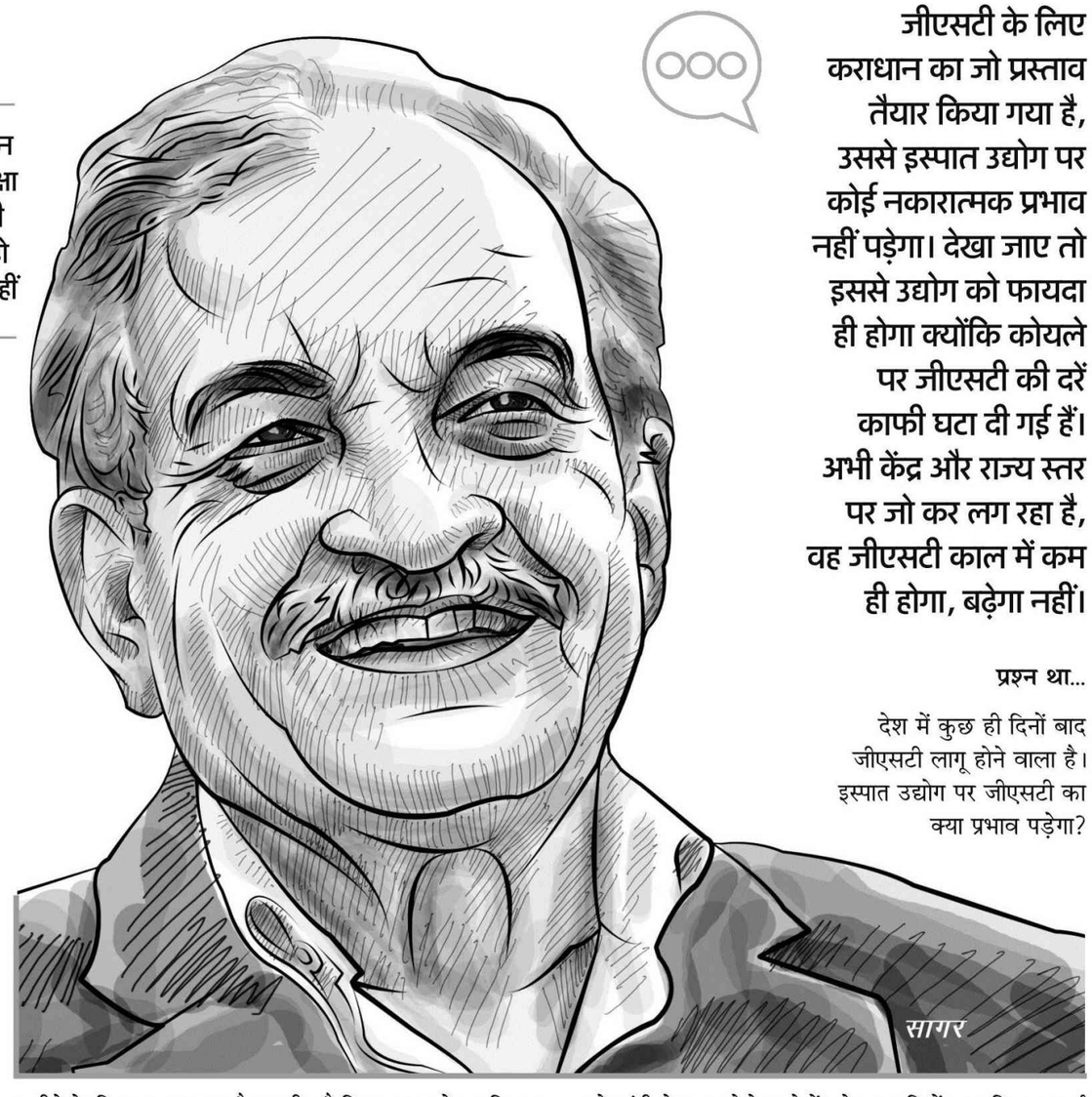

जीएसटी के लिए कराधान का जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उससे इस्पात उद्योग पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखा जाए तो इससे उद्योग को फायदा ही होगा क्योंकि कोयले पर जीएसटी की दरें काफी घटा दी गई हैं। अभी केंद्र और राज्य स्तर पर जो कर लग रहा है, वह जीएसटी काल में कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं।

प्रश्न था...

देश में कुछ ही दिनों बाद जीएसटी लागू होने वाला है। इस्पात उद्योग पर जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ेगा?